



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 9 जनवरी, 1998/19 पौष, 1919

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

विधायी (अंग्रेजी) शाखा

अधिसूचना

शिमला-2, 9 जनवरी, 1998

संख्या एल0 एल0 आर0-डी0(6) 19/97-लेजिस.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 9-1-98 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश

पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1997 (1997 का विधेयक संख्यांक 17) को 1998 के हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक 1 के रूप में, संविधान के अनुच्छेद 313(3) के अधीन उससे प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-,
सचिव।

1998 का अधिनियम संख्यांक 1.

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1997

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 9 जनवरी, 1998 को यथा अनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का 4) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-ड के खण्ड 4 के उप-खण्ड (ख) के अधीन यथा अपेक्षित संसद द्वारा अधिनियमित पंचायत (एक्टिंग नटू दि शेड्यूल एरियाज) ऐक्ट, 1996 के उपबन्धों द्वारा संविधान के अनुच्छेद 244 के खण्ड (1) में यथा निर्दिष्ट अधिसूचित क्षेत्रों में ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन, पंचायतों में सम्बन्धित भारत के संविधान के भाग 9 के उपबन्ध विस्तारित किए जाते हैं;

और हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 के उपबन्ध, राज्य में ऐसे अनुसूचित क्षेत्रों को लागू किए जाने में, 1996 के उक्त केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 40 के उपबन्धों के अनुकूल लागू जाने हैं ;

भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1997 है ।

संक्षिप्त नाम
और
प्रारम्भ ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

1994 का 4

2. पंचायती राज अधिनियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 1 में,—

धारा 1 का
संशोधन ।

(क) पार्श्व शीर्षक में शब्द “विस्तार” के पश्चात् चिह्न और शब्द “लागू होना” अन्तःस्थापित किए जाएंगे ; और

(ख) उप-धारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“(2-क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 के खण्ड (1) में यथा निर्दिष्ट राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों में इस अधिनियम के अध्याय 6-क के उपबन्धों के अधधीन, इस अधिनियम के शेष उपबन्ध लागू होंगे ।”

3. मूल अधिनियम के अध्याय-6 के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय अन्तःस्थापित

अध्याय 6-क
का अन्तः
स्थापन ।

किया जाएगा, अर्थात्:—

“अध्याय-6-क

अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों से सम्बन्धित विशेष उपबन्ध ।

97-क. इस अध्याय का लागू होना.—(1) इस अध्याय के उपबन्ध, राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में गठित ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को लागू होंगे ।

(2) इस अध्याय के उपबन्ध, इस अधिनियम में अन्यत्र उससे असंगत, किसी बात पर अभिभावी होंगे ।

97-ख. अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम की घोषणा.—धारा 3 के प्रयोजनों के लिए, गांव साधारणतया, समुदाय या समुदायों में समाविष्ट उसके आवास या आवासों के समूह या हैमलेट या हैमलेटों के समूहों से गठित होगा और जो परम्पराओं और रूढ़ियों के अनुसार अपने कार्यकलाप का प्रबन्ध करते हैं ;

97-ग. ग्राम सभा के कृत्य.—(1) प्रत्येक ग्राम सभा, लोगों की परम्पराओं और रूढ़ियों, उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक सम्पदाओं और तत्समय प्रवृत्त किसी विधि का अहित किए बिना, विवादों के रूढ़िक समाधान की प्रक्रिया के अभिरक्षण और परिरक्षण करने के लिए मक्षम होगी ।

(2) प्रत्येक ग्राम सभा,—

(i) ग्राम स्तर पर, ग्राम पंचायत द्वारा सागाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को कार्यान्वित किए जाने से पूर्व ऐसी योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं का अनुमोदन करेगी ;

(ii) गरीबी जन्मूलन और अन्य कार्यक्रमों के अधीन लाभार्थियों के रूप में व्यक्तियों की पहचान करने या चयन करने के लिए उत्तरदायी होगी ।

(3) उप-धारा (2) में निर्दिष्ट योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए पंचायत द्वारा निधियों के उपयोग का प्रत्येक ग्राम पंचायत ग्राम सभा से प्रमाणन अभिप्राप्त करेगी ।

97-घ. पंचायतों में पदाधिकारियों के लिए स्थानों का आरक्षण.—अनुसूचित क्षेत्रों की प्रत्येक ग्राम पंचायत और पंचायत समिति में स्थानों का आरक्षण, यथास्थिति, उस ग्राम पंचायत या पंचायत समिति के समुदायों की जनसंख्या के अनुपात में होगा :

परन्तु अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण स्थानों की कुल संख्या के आधे से कम नहीं होगा :

परन्तु यह और कि ग्राम पंचायत के प्रधानों और पंचायत समितियों के अध्यक्षों के सभी स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होंगे ।

97-ङ. व्यक्तियों का नामनिर्देशन.—सरकार, ऐसी अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित व्यक्तियों को, जिनका, यथास्थिति, पंचायत समितियों या जिला परिषदों में प्रतिनिधित्व नहीं है, नाम-निर्दिष्ट कर सकेगी :

परन्तु ऐसा नामनिर्देशन, यथास्थिति, पंचायत समिति या जिला परिषद् में निर्वाचित कुल सदस्यों के दसवें भाग से अधिक नहीं होगा ।

97-च. अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का अर्जन.—अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजनाओं के विभाग के लिए भू-अर्जन और अनुसूचित क्षेत्रों में ऐसी परियोजनाओं द्वारा विस्थापित व्यक्तियों के पुनः स्थापन या पुनर्वास से पूर्व, ग्राम सभा में परामर्श किया जाएगा । अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजनाओं के वास्तविक योजना और कार्यान्वयन को राज्य स्तर पर समन्वित किया जाएगा ।

97-छ. अनुसूचित क्षेत्रों में लघु जल निकायों का प्रबन्धन.—अनुसूचित क्षेत्रों में लघु जल निकायों की योजना और प्रबन्धन, यथास्थिति, ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों या जिला परिषदों को, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, सीपा जाएगा ।

97-ज. अनुसूचित क्षेत्रों में लघु खनिज.—(1) अनुसूचित क्षेत्रों में लघु खनिजों के लिए, पूर्वोक्त अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा अनुदत्त करने से पूर्व, ग्राम सभा द्वारा, ऐसी रीति में जैसी विहित की जाए, की गई सिफारिशों को ध्यान में रखा जाएगा ।

(2) नीलामी द्वारा लघु खनिजों के विदोहन की रियायत देने के लिए ग्राम सभा को, ऐसी रीति में जैसी विहित की जाए, की गई पूर्व सिफारिश को ध्यान में रखा जाएगा ।

97-झ. (1) ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों की शक्तियों और कृत्य.—(1) यथा स्थिति, ग्राम पंचायत या ग्राम सभा, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन ऐसी रीति में और उस विस्तार तक जो निम्नलिखित विषयों के बारे में विहित की जाए, करेगी, अर्थात्:—

- (क) मद्यनिषेध का प्रवर्तन या किसी मादक पदार्थ के विक्रय और उपभोग का विनियमन या निर्वन्धन ;
- (ख) लघु वन उपज का स्वामित्व ;
- (ग) ग्रामीण मण्डियों, चाहे किसी भी नाम से पुकारी जाएं, का प्रबन्धन ; और
- (घ) अनुसूचित जनजाति में साहूकारी पर नियन्त्रण ।

(2) पंचायत समिति, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन ऐसी रीति में और उस विस्तार तक, जो निम्नलिखित विषयों के बारे में विहित किया जाए, करेगी, अर्थात्:—

- (क) सभी सामाजिक क्षेत्रों में संस्थाओं और कृत्यकारियों पर नियन्त्रण ; और
- (ख) जनजातीय उप-योजनाओं सहित ऐसी योजनाओं के लिए स्थानीय योजना और सम्पदाओं पर नियन्त्रण ।”

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 1 of 1998.

THE HIMACHAL PRADESH PANCHAYATI RAJ (SECOND AMENDMENT) ACT, 1997

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 9TH JANUARY, 1998)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 4 of 1994).

WHEREAS the provisions of Part IX of the Constitution of India relating to Panchayats are extended subject to such exceptions and modifications to the scheduled areas as referred to in clause (1) of Article 244 of the Constitution by the provisions of the Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996 enacted by the Parliament as required under sub-clause (b) of clause (4) of Article 243M of the Constitution of India ;

AND WHEREAS the provisions of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 have to be brought in tune with the provisions of the said Central Act No. 40 of 1996 in their application to such scheduled areas in the State ;

BE it enacted by the Himachal Pradesh Legislative Assembly in the Forty-eighth Year of the Republic of India, as follows :—

Short title
and com-
mencement.

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Second Amendment) Act, 1997.

(2) It shall come into force on such date as the Government may, by notification, appoint.

Amend-
ment of
section 1.

2. In section 1 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (hereinafter referred to as the principal Act),—

4 of 15

(a) in the marginal heading, after the word “extent”, the sign and word, “application”, shall be inserted; and

(b) after sub-section (2), the following sub-section shall be inserted, namely:—

“(2A) In their application to the scheduled areas in the State as referred to in clause (1) of Article 244 of the Constitution of India, the remaining provisions of this Act shall apply, subject to the provisions of Chapter VI-A of this Act.”

Insertion
of Chapter
VI A.

3. After Chapter VI of the principal Act, the following Chapter shall be inserted, namely:

"CHAPTER VI-A

SPECIAL PROVISIONS RELATING TO THE GRAM PANCHAYATS, PANCHAYAT SAMITIS AND ZILA PARISHADS LOCATED IN THE SCHEDULED AREAS

97-A. Application of this Chapter.—(1) The provisions of this Chapter shall apply to the Gram Panchayats, Panchayat Samitis and Zila Parishads constituted in the scheduled areas in the State.

(2) The provisions of this Chapter shall prevail over anything inconsistent therewith elsewhere in this Act.

97-B. Declaration of village in scheduled areas.—For the purposes of section 3, a village shall ordinarily consist of a habitation or a group of habitations or a hamlet or a group of hamlets thereof comprising a community or communities and managing their affairs in accordance with traditions and customs.

97-C. Functions of Gram Sabha.—(1) Every Gram Sabha shall be competent to safeguard and preserve the traditions and customs of the people, their cultural identity, community resources and without detriment to any law for the time being in force, the customary mode of dispute resolution.

(2) Every Gram Sabha shall,—

(i) approve plans, programmes and projects for social and economic development before such plans, programmes and projects are taken up for implementation by the Gram Panchayat, at the village level ;

(ii) be responsible for the identification or selection of persons as beneficiaries under poverty alleviation and other programmes.

(3) Every Gram Panchayat shall obtain from the Gram Sabha, a certification of utilisation of funds by that Panchayat for the plans, programmes and projects referred to in sub-section (2).

97-D. Reservation of seats of office bearer in Panchayats.—The reservation of seats in the scheduled areas to every Gram Panchayat and Panchayat Samiti shall be in proportionate to the population of the communities in that Gram Panchayat or the Panchayat Samiti, as the case may be :

Provided that the reservation for the Scheduled Tribes shall not be less than one-half of the total number of seats :

Provided further that all seats of Pradhan of Gram Panchayats and Chairman of Panchayat Samitis shall be reserved for the Scheduled Tribes.

97-E. Nomination of persons.—The Government may nominate persons belonging to such Scheduled Tribes who have no representation

in Panchayat Samitis or the Zila Parishad, as the case may be :

Provided that such nomination shall not exceed one-tenth of the total members to be elected in the Panchayat Samiti or Zila Parishad, as the case may be.

97-F. Acquisition of land in the scheduled areas.—The Gram Sabha shall be consulted before making the acquisition of land in the scheduled areas for development of projects and before re-settling or rehabilitating persons evicted by such projects in the scheduled areas; the actual planning and implementation of the projects in the scheduled areas shall be co-ordinated at the State Level.

97-G. Management of minor water bodies in the scheduled areas.—Planning and management of minor water bodies in the scheduled areas shall be entrusted to Gram Panchayats, Panchayat Samitis or the Zila Parishads, as the case may be, in such manner as may be prescribed.

97-H. Minor minerals in the scheduled areas.—(1) The recommendations of the Gram Sabha, made in such manner as may be prescribed, shall be taken into consideration prior to grant of prospecting license or mining lease, for minor minerals in the scheduled areas.

(2) The prior recommendation of the Gram Sabha, made in such manner as may be prescribed, shall be taken into consideration for grant of concession for the exploitation of minor minerals by auction.

97-I. Powers and functions of Gram Panchayats and Panchayat Samitis.—(1) The Gram Panchayat or as the case may be, the Gram Sabha shall exercise such powers and perform such functions in such manner and to such extent as may be prescribed in respect of the following matters, namely: —

- (a) the ownership of minor forest produce;
- (b) enforcement of prohibition or regulation or restriction of the sale and consumption of any intoxicant;
- (c) management of village markets by whatever name called; and
- (d) exercising control over money lending to the Scheduled Tribes.

(2) The Panchayat Samiti shall exercise such powers and perform such functions in such manner and to such extent as may be prescribed, in respect of the following matters, namely:—

- (a) exercising control over institutions and functionaries in all social sectors; and
- (b) control over local plans and resources for such plans including tribal sub-plans.”